



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 632) पटना, सोमवार, 26 जुलाई 2021

विधि विभाग

v f/ k p u k

26 जुलाई 2021

fcglj fof/ki nk/ldlj h'apuc) r k/fu; eloylj 2021

सं0 सी0/ई0एच0-07/2017-3909/जे0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय, अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों इत्यादि के लिए बिहार राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुपरक रीति से, बिहार राज्य के विभिन्न कोर्ट के विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता तंत्र का उपबंध करने तथा उनकी वचनबद्धता, पारिश्रमिक, कर्तव्य एवं अन्य निर्बंधन और शर्तों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या-16891/2017 (विजय कुमार विमल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक-16.07.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

- (1) यह नियमावली बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन यथापरिभाषित अधिवक्ता;
- (ख) "महाधिवक्ता" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद-165 के अधीन बिहार राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति और इस रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति इसमें शामिल है;
- (ग) "अभिलेख अधिवक्ता" से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के लागू नियमों के अनुसार अभिलेख अधिवक्ता;
- (घ) "सहायक अधिवक्ता" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-9 के अधीन अधिवक्ता जो विधि पदाधिकारी न हो, किंतु विधि पदाधिकारी को सहायता उपलब्ध करने हेतु वचनबद्ध हो;
- (ङ) "कोर्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-3 में विनिर्दिष्ट विधि पदाधिकारियों की कोर्ट और इसमें विधि पदाधिकारियों के अन्य कोर्ट शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाय;
- (च) "वचनबद्धकर्ता प्राधिकार" से अभिप्रेत है सरकार;

- (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (ज) "सरकारी काउंसिल" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-5(4) के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता;
- (झ) "विधि पदाधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में विधि पदाधिकारी के रूप में, नियमानुसार, वचनबद्ध अधिवक्ता और इसमें विशेष लोक अभियोजक अथवा विशेष काउंसिल शामिल है;
- (ञ) "लोक अभियोजक" से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय अथवा सेशन डिविजन के लिए लोक अभियोजक होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-24 के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता और इसमें अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक शामिल है;
- (ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-5 के अधीन गठित समिति;
- (ठ) "खोजबीन समिति" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-4 के अधीन गठित खोजबीन समिति;
- (ड) "विशेष काउंसिल" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-13 के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता अथवा वरीय अधिवक्ता।
- (ढ) "शोध काउंसिल" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-14 के अधीन वचनबद्ध कोई अधिवक्ता।
- (ण) "विशेष लोक अभियोजक" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-24(8) के अधीन अधिवक्ता अथवा अन्य किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से प्रावधानित।

3. विधि पदाधिकारियों की कोटि।—

- (1) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को पटना उच्च न्यायालय के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथा:—
 - (क) अपर महाधिवक्ता;
 - (ख) राजकीय अधिवक्ता;
 - (ग) सरकारी वकील;
 - (घ) स्थायी सलाहकार;
 - (ङ) लोक अभियोजक;
 - (च) अपर लोक अभियोजक;
 - (छ) अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल)
- (2) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथा:—
 - (क) स्थायी सलाहकार;
 - (ख) अपर स्थायी सलाहकार
- (3) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथा:—
 - (क) लोक अभियोजक;
 - (ख) सरकारी वकील;
 - (ग) अपर लोक अभियोजक;
 - (घ) सहायक सरकारी वकील
- (4) विधि पदाधिकारियों की उपर्युक्त कोटि तथा प्रत्येक कोटि में नियुक्त होने वाले विधि पदाधिकारियों की संख्या, समय-समय पर, आवश्यकतानुसार, महाधिवक्ता के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर, नियत और/अथवा उपांतरित की जाएगी।
- (5) उपर्युक्त उपनियम (4) के अधीन निर्धारण करते समय, सरकार, विभिन्न पहलूओं, यथा सरकार को अन्तर्ग्रस्त करने वाले विधिक मामलों के कार्यबोझ, न्यायालयों की कुल संख्या (स्वीकृत और कार्यरत), अन्तर्ग्रस्त कार्य की प्रकृति, विषय-वस्तु की विशेषज्ञता तथा कोई अन्य सुसंगत सामग्री अथवा पहलू, जिसे उपर्युक्त समझे, पर विचार कर सकेगी।
- (6) सरकार, इस नियमावली के अधीन पदों के विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के लिए, वचनबद्धकर्ता प्राधिकार होगी और इस प्रकार वचनबद्ध विधि पदाधिकारी सरकार के प्रसादपर्यंत उन पदों को धारित करेंगे।

4. खोजबीन समिति।—

- (1) पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में नियम-3(1)(क) से (घ) तथा नियम-3(2) के अधीन विधि पदाधिकारियों की विभिन्न कोटि की वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं के नामों की खोजबीन करने तथा पैनल तैयार करने के लिए एक खोजबीन समिति होगी। यह समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी यथा:—

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---------|
| (क) | महाधिवक्ता, बिहार | — | अध्यक्ष |
| (ख) | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | — | सदस्य |
| (ग) | प्रधान सचिव, गृह (पुलिस) विभाग | — | सदस्य |
| (घ) | सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग | — | सदस्य |
- (2) खोजबीन समिति इस नियमावली के अधीन उपवर्णित पात्रता का मापदण्ड तथा उसके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा और उपयुक्तता के आधार पर इस नियमावली के नियम-3(4) के अधीन यथा विनिश्चित संख्या से अनधिक दोगुनी संख्या में अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और विधि विभाग के माध्यम से, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिए, अपनी अनुशंसा के साथ उसे चयन समिति को भेज देगी।
- (3) खोजबीन समिति, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं की रजामंदी मांगने तथा उनके नामों का पैनल तैयार करने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विनिर्मित करेगी।
- खोजबीन समिति, नियम-4(2) के अधीन अधिवक्ताओं के योग्यता की जाँच हेतु उनके विधिक क्षेत्र एवं उस क्षेत्र में उनके कार्य करने की अवधि, सरकार की ओर से वादों के संचालन में अनुभव एवं न्यायालयी उपस्थिति, प्रारूपण में दक्षता, प्रतिवेदित एवं अप्रतिवेदित न्याय निर्णय के संबंध में सम्बद्ध को दिये जाने वाले आवश्यक सूचना संबंधी कार्य आदि को महत्व देने के लिए स्वयं अपनी दिशा-निर्देश विनिर्धारित करेगी।

5. चयन समिति तथा वचनबद्धता।—

- (1) यह चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी, यथा :—
- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------------|
| (क) | विधि मंत्री | — | अध्यक्ष |
| (ख) | महाधिवक्ता, बिहार | — | सदस्य |
| (ग) | सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग | — | सदस्य सचिव |
- (2) चयन समिति, इस नियमावली के नियम-4(2) के अधीन खोजबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा प्राप्त होने पर, इस नियमावली में उपवर्णित पात्रता, मानदण्ड तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा और उपयुक्तता के आधार पर पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिए सरकार को अनुशंसा करेगी।
- (3) उपनियम-(2) के अधीन चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर, सरकार, आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में पदों की विभिन्न कोटि में विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता करेगी तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों को, जो इस संबंध में सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाय, शामिल करते हुए विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता का आदेश निर्गत करेगी।
- (4) व्यवहार न्यायालय को छोड़कर, न्यायाधिकरण या किसी विधि द्वारा या के अधीन गठित न्यायनिर्णायक निकायों या राज्य के किसी अन्य विधि न्यायालय या माध्यस्थों या सरकार के किसी विशिष्ट विभाग के लिए विशेष रूप से अपेक्षित मामले में सरकारी काउंसल महाधिवक्ता के अनुशंसा पर वचनबद्ध होंगे। महाधिवक्ता योग्य अधिवक्ताओं के नाम की अनुशंसा उनके अनुभव, योग्यता, प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा, मेधा तथा उपयुक्तता के आधार पर विधि विभाग के माध्यम से चयन समिति को सरकारी काउंसल के रूप में वचनबद्ध करने के लिए समर्पित करेंगे, जिसकी संख्या, वचनबद्ध होनेवाले अधिवक्ता की संख्या के दोगुनी से अधिक नहीं होगी।
- (5) (i) जिला समाहर्ता, संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, इस नियमावली के अधीन दी गई पात्रता मानदण्ड तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा तथा उपयुक्तता के आधार पर, अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और उसे सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग को सुपुर्द कर देगी।
- (ii) जिला समाहर्ता द्वारा उस प्रकार अग्रसारित सूची इस नियमावली के नियम-5(1) के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी और चयन समिति, इस नियमावली के नियम-3(3)(ख) एवं 3(3)(घ) में यथोल्लिखित पदों की विभिन्न कोटि में सरकार द्वारा वचनबद्धता के लिए, इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित पात्रता तथा अर्हताओं तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा तथा उपयुक्तता के आधार पर भी अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी। चयन समिति द्वारा ऐसी अनुशंसा किए जाने पर, सरकार, आदेश द्वारा, बिहार के व्यवहार न्यायालयों में पदों की विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों का वचनबद्धता करेगी।

(iii) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी पटना उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल) तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की क्रमशः धारा-24(1) एवं धारा-24(3), 24(4), 24(7) के प्रावधानों के अनुसार ही की जायेगी। इसी प्रकार पटना उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक तथा व्यवहार न्यायालयों में, किसी मामले अथवा किसी वर्ग के मामलों के लिए या विशेष अधिनियम के तहत विशिष्ट मामलों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-24(8) के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

परन्तु राज्य के व्यवहार न्यायालयों के मामले में लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजकों के चयन में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-24(6) (यथा संशोधित बिहार अधिनियम-16 1984) के प्रावधान भी लागू होंगे।

(6) खोजबीन समिति अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा करते समय, पदों की विभिन्न कोटि में उनकी वचनबद्धता के लिए इस बात का ध्यान रखेगी कि इस प्रकार अनुशंसित अधिवक्ताओं की सूची में समाज के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व अंतर्विष्ट है।

6. पात्रता— विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्ध किये जाने हेतु कोई अधिवक्ता—

- (क) भारत का नागरिक और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद् से पंजीकृत होगा;
- (ख) अभिहित वरीय अधिवक्ता अथवा अभिलेख अधिवक्ता होगा, जो पटना उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा विधि न्यायालय में व्यवसाय कर रहा हो अथवा कोई अधिवक्ता जो बिहार के व्यवहार न्यायालय में व्यवसाय कर रहा हो;
- (ग) अपनी-अपनी कोटि के विरुद्ध व्यवसाय का निम्नलिखित वर्षों का अनुभव रखता हो तथा उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें वचनबद्धता की जानी हो, कम से कम तीन पूर्व वित्तीय वर्षों का आयकर निर्धारित भी रहा हो;
 - (i) पटना उच्च न्यायालय के लिए अपर महाधिवक्ता हेतु, वह न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर चुका हो अथवा पटना उच्च न्यायालय का एक अभिहित वरीय अधिवक्ता रह चुका हो;
 - (ii) भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थायी सलाहकार के लिए, वह भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (iii) पटना उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय में अपर स्थायी सलाहकार के लिए, वह पटना उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय में क्रम 1: उस न्यायालय के लिए जिसके लिए वचनबद्धता की जानी हो, न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (iv) पटना उच्च न्यायालय के लिए स्थायी सलाहकार हेतु वह पटना उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (v) पटना उच्च न्यायालय के लिए सरकारी वकील हेतु, वह पटना उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (vi) बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए सरकारी वकील हेतु, वह बिहार के व्यवहार न्यायालय में न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (vii) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए लोक अभियोजक हेतु वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (viii) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए अपर लोक अभियोजक हेतु वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;
 - (ix) बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए सहायक सरकारी वकील हेतु वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो।

7. वचनबद्धता के लिए निरर्हताएँ।—कोई भी अधिवक्ता या वरीय अधिवक्ता इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्ध होने अथवा बने रहने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में निरर्हति होगा—

- (1) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामले में किसी प्राइवेट व्यक्ति से ब्रीफ स्वीकार करने से विवर्जित है;
 - (2) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी सिविल मामले में किसी प्राइवेट व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार कर सकेगा बशर्ते कि उसकी स्वीकार्यता विधि पदाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप न करती हो और प्राइवेट पक्षकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाले विवादों से मुख्य रूप से संबंधित हो तथा सरकार अथवा उसके पदधारियों को अंतर्ग्रस्त करने वाला न हो;
 - (3) कोई भी विधि पदाधिकारी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अथवा किसी ऐसे मामले में जिसमें उस व्यक्ति के हित सरकार अथवा उसके पदधारियों के प्रतिकूल हो, उपस्थित नहीं होगा अथवा उसे विधिक सलाह नहीं देगा;
 - (4) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी व्यक्ति से, चाहे वह अर्जीदार अथवा प्रत्यर्थी हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधान मंडल या संसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गयी किसी निर्वाचन अर्जी की कार्यवाही में किसी व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा;
 - (5) कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के राज्य विधान मंडल अथवा किसी नगर निगम अथवा नगर परिषद, पंचायत अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो, जब तक वह वैसा पद धारित करता है, विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा;
 - (6) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी परिनियम या अन्यथा के अधीन अथवा द्वारा गठित राज्य के किसी परिकरण को, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, प्राधिकार इत्यादि शामिल हैं, विधिक सलाह नहीं देगा अथवा से ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा जहाँ वैसी सलाह, स्वीकार्यता, उपस्थिति सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिकूल हो;
 - (7) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी व्यक्ति, निकाय, संगठन को विधिक सलाह देना, ब्रीफ प्रतिधारित करना अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित होना जारी नहीं रखेगा जिससे सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित, इस नियमावली के अधीन वचनबद्ध होने के बाद, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता हो;
 - (8) यदि कोई विधि पदाधिकारी अधिवक्ता न रह जाय अथवा यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध में सिद्धदोष हो जाय।
8. विधि पदाधिकारी का कर्तव्य।— किसी विधि पदाधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—
- (क) राज्य सरकार को ऐसे विधिक मामलों में सलाह देना और विधिक चरित्र के ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार अथवा महाधिवक्ता द्वारा, समय-समय पर, उसे निर्देशित अथवा समनुदेशित किए जाय;
 - (ख) राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों/पदधारियों की ओर से पटना उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय, किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य विधि न्यायालय, के समक्ष महाधिवक्ता द्वारा यथा आवंटित या यथा निदेशित सभी कार्यवाहियों में जिसमें सरकार का संबंध एक पक्षकार के रूप में हो अथवा वह अन्यथा हितबद्ध हो, असफल रहे बिना उपस्थित होना तथा अभियोजित या प्रतिरक्षण करना;
 - (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो भारत के संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन विधि पदाधिकारी को प्रदत्त हों।

9. सहायक अधिवक्ता।—

- (1) एक अभिलेख अधिवक्ता, जो पटना उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम 3 वर्षों से व्यवसाय में रहा हो, उस संख्या में और उस शुल्क पर, जो महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय, इस नियमावली के नियम—(8)(ख) के अधीन विधि पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन में इस नियमावली के नियम—(3)(1)(क) से (घ) तथा (3)(2) के अधीन महाधिवक्ता या विधि पदाधिकारी के साथ उनकी सहायता के लिए सहायक अधिवक्ता के रूप में वचनबद्ध होने योग्य होगा।

10. विधि पदाधिकारियों की मुक्ति।—

- (1) इस नियमावली के अधीन पदों की विभिन्न कोटि के लिए वचनबद्ध या को धारित करने वाले विधि पदाधिकारी अथवा सरकार की इच्छा से इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई अधिवक्ता, यदि नियम—6 के अधीन पात्र न पाया जाय अथवा नियम—7 के अधीन निरर्हता से ग्रस्त पाये जाने पर अथवा इस नियमावली के नियम—8 के अधीन कर्तव्यों के अनुपालन में असफल रहने पर, महाधिवक्ता के परामर्श से या सरकार द्वारा किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा। विधि पदाधिकारी इस संबंध में महाधिवक्ता को एक माह की सूचना देकर स्वयं को मुक्त कर सकेगा।

11. अनुपालन का पुनर्विलोकन।—

- (i) पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए वचनबद्ध होने वाले इस नियमावली के अधीन यथोल्लेखित विभिन्न कोर्ट के विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा वैसा मूल्यांकन, उनके कर्तव्यों के अनुपालन के अंकन के लिए, सरकार के पास भेज दिया जायेगा और सरकार ऐसे विधि पदाधिकारियों को, महाधिवक्ता के परामर्श से, मुक्त कर देगी जिसका अनुपालन इस नियमावली के नियम-8 के अधीन कर्तव्यों के अनुपालन में उनकी असफलता अथवा संतोषप्रद न रहा हो;
- (ii) राज्य के व्यवहार न्यायालय के लिए वचनबद्ध होने वाले इस नियमावली के अधीन यथोल्लेखित विभिन्न कोर्ट के विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा वैसा मूल्यांकन उनके कर्तव्यों के अंकन के लिए सरकार के पास भेज दिया जायेगा तथा सरकार महाधिवक्ता के परामर्श से, ऐसे विधि पदाधिकारियों को मुक्त कर देगी जिनका प्रदर्शन इस नियमावली के नियम-8 के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में, उनकी असफलता के कारण संतोषजनक न हो।

12. प्रतिधारण शुल्क, शुल्क और भत्ते।— नियम-8 में यथोल्लिखित कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किसी विधि पदाधिकारी को प्रतिधारण शुल्क, शुल्क और भत्ते सहित ऐसी शुल्क संदत्त की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाय।

13. विशेष वचनबद्धता।— इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाधिवक्ता को, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए, ऐसे निर्बंधनों एवं शुल्क पर, जो प्रशासी विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए किसी अधिवक्ता को, जो इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी न हो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण मामलों में विशेष काउंसिल के रूप में वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

14. शोध काउंसिल।— इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी महाधिवक्ता को अधिकाधिक पाँच की संख्या में अनधिक 3 वर्षों की अवधि के लिए उन निर्बंधनों और शर्तों पर जो विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए, यथा विधायी प्रारूपण, तकनीकी विधि, विधीक्षा, सरकार के लिए विशेष रूप से सांविधानिक, कराधान, राजस्व एवं आपराधिक मुद्दे अंतर्गस्त करने वाले मामलों के लिए व्यापक शोध जैसे सरकार के लिए विशिष्ट प्रकृति के विधिक कार्य को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ताओं को वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

15. व्यावृत्ति एवं अभिभावी प्रभाव।—

- (प) यह नियमावली विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित विभिन्न परिनियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का पूरक होगी।
- (पप) इस नियमावली के प्रवृत्त हाने के पूर्व उसमें उपबंधित विषयों के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई/निर्गत इस नियमावली के विरुद्ध किसी बात अथवा विधि परामर्शी नियमावली, 1946 में अंतर्विष्ट विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित किसी बात का प्रभाव इस नियमावली पर नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

26 जुलाई 2021

सं० सी०/ई०एच०-07/2017-3909/जे० निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

The 26th July 2021

Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2021

No. C/EH-07/2017-3909/J—In exercise of powers under Article-162 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules to provide for system of engagement of Law Officers for the State of Bihar for the Patna High Court, the Supreme Court of India, other Courts of Law, Tribunals, etc. in a transparent, fair and objective manner and to regulate their engagement, remuneration, duties and other terms and conditions and for matters connected therewith and incidental thereto:-

1. Short title and commencement.—

- (1) These Rules may be called the Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) **"Advocate"** means an advocate as defined under the Advocates Act, 1961;
- (b) **"Advocate General"** means a person appointed under Article-165 of the Constitution of India as Advocate General for the state of Bihar and includes any person appointed to act temporarily as such;
- (c) **"Advocate on Record"** means an Advocate on Record as per the applicable Rules of the Patna High Court and the Supreme Court of India;
- (d) **"Assistant Counsel"** means an Advocate not being a Law Officer but engaged to provide assistance to Law Officer under Rule-9 of these Rules;
- (e) **"Category"** means the category of post of Law Officers specified in Rule 3 of the Rules and includes such other categories of Law Officers, as may be determined by the Government from time to time;
- (f) **"Engaging Authority "** means the Government;
- (g) **"Government"** means the Government of the State of Bihar;
- (h) **"Government Counsel"** means an Advocate engaged under Rule-5(4) of these Rules;
- (i) **"Law Officers"** means an Advocate engaged under these Rules as a Law officer in the Office of the Advocate General by the Government and includes a Special Public Prosecutor or a Special Counsel;
- (j) **"Public Prosecutor"** means an Advocate appointed under section-24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to be a Public Prosecutor for the Patna High Court or for the Sessions Division and includes Additional Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor (Senior Panel) and Special Public Prosecutor;
- (k) **"Selection Committee"** means a committee constituted under Rule-5 of these Rules.
- (l) **"Search Committee"** means a Committee constituted under Rule-4 of these Rules;
- (m) **"Special Counsel"** means an Advocate or a Senior Advocate engaged under Rule 13 of these Rules.
- (n) **"Research Counsel"** means an Advocate engaged under Rule-14 of these Rules.
- (o) **"Special Public Prosecutor"** means an advocate engaged under Section-24(8) of the Code of Criminal Procedure, 1973 or any other Special Act specially provided therein.

3. Categories of Law Officers.—

- (1) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Patna High Court, namely:-
 - (a) the Additional Advocate General;
 - (b) the Government Advocate;
 - (c) the Government Pleader;
 - (d) the Standing Counsel;
 - (e) the Public Prosecutor;
 - (f) the Additional Public Prosecutor;
 - (g) the Additional Public Prosecutor (Senior Panel);
- (2) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Supreme Court of India, namely:-
 - (a) the Standing Counsel;
 - (b) the Additional Standing Counsel;
- (3) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Civil Courts of Bihar, namely:-
 - (a) the Public Prosecutor.
 - (b) the Government Pleader.
 - (c) the Additional Public Prosecutor.
 - (d) the Additional Government Pleader.
- (4) The above categories of Law Officers and the number of Law Officers to be engaged under each categories shall be fixed and/or modified, from time to time as required, by the Government based on an assessment made by the Government in consultation with the Advocate General.
- (5) The Government while making assessment under sub-Rule(4) above may take into consideration of various aspect, namely, the workload of legal cases involving the Government, the total number of Courts (sanctioned and working), the nature of work involved, specialization in subject matters and any other relevant material or aspect, as it deems fit.
- (6) The Government shall be the Engaging Authority for the Law Officers belonging to the various categories of posts under these Rules and the Law Officers so engaged shall hold such posts during the pleasure of the Government.

4. Search Committee.—

- (1) There shall be a Search Committee for searching the names and preparing the panel of Advocates for making recommendation to the Selection Committee for engagement of different categories of Law Officers under the Rule-3(1)(a) to (d) and 3(2) in the Patna High Court and in the Supreme Court of India. This Committee Shall consist of the following, namely:-

(a) The Advocate General, Bihar	Chairman
(b) The Principal Secretary, General Administration Department	Member
(c) The Principal Secretary, Home (Police) Department	Member
(d) The Secretary-Cum-Legal Remembrancer, Law Department	Member
- (2) The Search Committee shall prepare a panel of names of Advocates, not more than upto twice the number as determined under Rule 3(4) of these

(3) The Search Committee shall formulate its own procedure for seeking willingness and preparation of the panel of the names of the advocates for engagement as Law Officers in the Patna High Court and the Supreme Court of India.

5. Selection Committee and Engagement.—

- (1) The Selection Committee shall consist of the following, namely:-
 - (a) The Minister-in-Charge, Law Department Chairman
 - (b) The Advocate General Member
 - (c) The Secretary-Cum-Legal Remembrancer, Member Secretary
Law Department
- (2) The Selection Committee, on receipt of the recommendation made by the Search Committee under Rule 4(2) of these Rules, shall recommend to the Government for engagement of such Advocates as Law Officers in Patna High Court and the Supreme court of India on the basis of the eligibility criteria set out under these Rules and their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability.
- (3) On the recommendations made by the Selection Committee under sub-Rule (2), the Government shall, by order, make the engagement of Law Officers to the various categories of posts in Patna High Court and the Supreme Court of India and shall issue order(s) of engagement of Law Officers including such terms and conditions as may be determined by the Government in this regard from time to time.
- (4) The Government counsel for Tribunals, other adjudicatory bodies constituted by or under any law or any other Court of law of the State, except the Civil Courts, or arbitrators or in case so specially required for any particular Department of the Government shall be engaged on the recommendation of the Advocate General. Advocate General will recommend the names of suitable Advocates, not more than up to twice the number of Advocate to be so engaged, on the basis of their experience, ability, integrity, experience, reliability, reputation, merit and suitability and submit the recommendation to the selection committee through the Law Department for engagement of such Advocates as Government Counsels.
- (5) (i) The District Magistrate, in consultation with the District and Sessions Judge for the concerned district, shall prepare a panel of names of Advocates on the basis of the eligibility criteria set out under these Rules and their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability and submit it to the Secretary-Cum-Legal Remembrancer, Law Department.

- (ii) The list so forwarded by the District Magistrate shall be placed before the Selection Committee constituted under Rule 5(1) of these Rules and based on the eligibility and qualifications as provided under these Rules and also their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability. The Selection Committee shall prepare a panel of names of Advocates for engagement by the Government on the categories of posts mentioned in Rule 3(3) of these Rules. On such recommendations made by the Selection Committee, the Government shall, by order, make engagement of Law Officers to the various categories of Posts in the Civil Courts of Bihar.
- (iii) Notwithstanding anything contained in these Rules the engagement of Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor (Senior Panel) in the Patna High Court and Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor in the Civil Courts of the State shall be made as per the provisions of section 24(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973. Similarly, the engagement of Special Public Prosecutor in the Patna High Court or in the Civil Courts for any class or class of cases or special offences under the Special Acts shall be made as per the provisions of Section 24(8) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Provided that in respect of such engagement of Public Prosecutors and Additional Public Prosecutors in the Civil Courts of the State the Provisions of Section 24(6) of the Code of Criminal Procedure, 1973 as substituted by Bihar Act 16 of 1984 shall also be applicable.

- (6) The Search Committee while making recommendation of the names of the Advocates for their engagement on various categories of posts shall have regard to the facts that the list of the Advocates so recommended contains proper representation of all sections of the society.

6. Eligibility.—

- (1) In order to be eligible to be engaged as a Law Officer, an Advocate shall be:-
 - (a) a citizen of India and registered with a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961; and
 - (b) a designated senior Advocate or an Advocate on record, who has been practicing in the Patna High Court or Supreme Court of India or an Advocate who has been practicing in the Civil Courts of Bihar;
 - (c) possesses the following standing in number of years of practice against the respective categories and being an income tax assessee for at least three financial years from the financial year in which engagement is to be made:-
 - (i) For an Additional Advocate General for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years or a designated Senior Advocate of the Patna High Court;

- (ii) For a Standing Counsel for the Supreme Court of India he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years in the Supreme Court of India;
- (iii) For a Government Advocate for the Patna High Court or For an Additional Standing Counsel for the Supreme Court of India he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years in the Patna High Court or in the Supreme Court of India respectively for that Court for which the engagement is to be made;
- (iv) For a Standing Counsel for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years in the Patna High Court;
- (v) For a Government Pleader for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years in the Patna High Court;
- (vi) For a Government Pleader for the Civil Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 07 years in the Civil Courts of Bihar;
- (vii) For a Public Prosecutor for the Patna High Court or for the Civil Courts of Bihar he has been in practice for not less than 07 years;
- (viii) For an Additional public Prosecutor for Patna High Court or for the Civil Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 07 years;
- (ix) For an Additional Government Pleader for the Civil Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 07 years in the Civil Courts of Bihar.

7. Disqualification for engagement.—An Advocate or a senior Advocate shall be disqualified from being engaged or to continue as Law Officer under these Rules in the following circumstances:-

- (1) a Law Officer who accepts brief from any private person in an criminal case in any court;
- (2) a Law Officer may accepts a brief from any private person for a civil case in any court provided that such acceptance does not interfere with the discharge of his duties as a Law Officer and relates solely to dispute involving private parties and not involving the Government or its officials.
- (3) an officer shall not appear for or give legal advice to private person or matter in which the interest of the person are likely to be adverse to that of the Government or its Officials;
- (4) a Law Officers shall not accept a brief from any person, whether a petitioner or respondent, in proceedings initiated in an Election Petition in connection with an Election to a Local Authority or the State Legislature or the Parliament;
- (5) a person, who is a member of the parliament or a Legislature of the State, a municipal Corporation, a Municipal Council, a Panchayat or any other Local Authority, shall not, as long as he hold that office, be eligible for engagement;

- (6) a law officer shall not give legal advice to or accept a brief from or appear in any Court of Law on behalf of any instrumentality of the State, constituted by or under any statute or otherwise, including various Universities, Boards, Corporations, Authorities etc, where such advice acceptance or appearance is in conflict with the interest of the Government or its Officials , either directly or indirectly;
- (7) a Law Officer shall not continue to give legal advice to or to retain brief from or appear in any Court of Law on behalf of any person, body, association, company etc which effects the interest of the Government or its Officials, either directly or indirectly, after being engaged under these Rules;
- (8) If the Law Officer ceases to be an and Advocate or is convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude.

8. Duties of Law Officer.— It shall be duties of a Law Officer:-

- (a) to give advice to the Government upon such matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time, be referred or assigned to him by the Government or the Advocate General.
- (b) to appear without fail on behalf of the Government and its Officials and either prosecute or defend all proceedings, as that case may be, before the Patna High Court or the Supreme Court or any other High Court or any other Courts of Law as allotted or as directed by the Advocate General, in which the Government is concerned as a party or is otherwise interested.
- (c) to discharge such other functions as are conferred on a Law Officer by or under the Constitution of India or any other Law for the time being in force.

9. Assistant counsels.—

- (1) An advocate on Record who have been in practice for not less than 3 Years in the High Court or Supreme Court shall be eligible for engagement as Assistant Counsel for rendering assistance to the Law Officers for the Patna High Court and Supreme Court of India in such number and as such fees, as may be decided by the Government on the recommendation of the Advocate General for being attached with the Advocate General or the Law Officer mentioned under Rule 3(1)(a) to (d) and 3(2) of these Rules for assisting the Law Officer in performance of their duties as Law Officers under Rule 8(b) of these Rules.

10. Disengagement of Law Officers.—The Law Officers engaged and holding the various categories of posts under these Rules or an Advocate engaged under these Rules at the pleasure of the Government shall be disengaged at any time by the Government in consultation with the Advocate General or if found to be not eligible as under Rule 6 or having found to have incurred disqualification as under Rule 7 or on failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules. The Law Officer may disengage himself after giving one month notice to the Advocate General in this regard.

11. Review of performance.—

- (i) The works of different categories of Law Officers engaged, as mentioned under these Rules, for the Patna High Court and the Supreme Court of India shall be assessed every year by the Advocate General and such assessment shall be sent to the Government for appraisal of their performance of duties and the Government shall disengage such Law Officers, in consultation with the Advocate General, Whose performance

has not been satisfactory on account of their failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules.

- (ii) The works of different categories of Law Officers engaged, as mentioned under these Rules, for the Civil Courts of the State shall be assessed every year by the District and Sessions Judge and the District Magistrate of the concerned District and such assessment shall be sent to the Government for appraisal of their performance of duties and the Government may disengage such Law Officers, in consultation with the Advocate General, whose performance has not been satisfactory on account of their failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules.

12. Retainer, Fee and other Allowances.—For performance of the duties as mentioned in Rule 8 a Law Officer shall be paid fee including retainer fee, and such other allowances as may be determined by the Government from time to time.

13. Special Engagement.—Notwithstanding anything contained in these Rules the Advocate General shall have the discretion to engage for the Patna High Court and the Supreme Court of India, on such terms and fee as may be fixed, in consultation with the Administrative Department and the Law Department, an Advocate for the Government as a Special Counsel who is not a Law Officer under these Rules, in case(s) involving important issue(s) for the Government.

14. Research Counsel.—Notwithstanding anything contained in these Rules the Advocate General shall have the discretion to engage upto a maximum of five in numbers for not more than the period of three years and on such terms and consolidated fee per month as may be fixed in consultation with the Law Department, Advocates for carrying out a specialized nature of the legal work for the Government, such as legislative drafting, techno legal vetting, comprehensive research for case(s) involving important issues for the Government, specially constitutional, taxation, revenue and criminal.

15. Saving and overriding effect.—

- (i) These Rules shall be supplemental to the provisions contained in different statutes regarding engagement of Law Officers.
- (ii) Anything contrary to these Rules made or issued by the Government in connection with the matters provided for herein prior to coming force of these Rules or anything contained in the Legal Remembrancer Rules, 1946 shall not have any effect and shall not stand saved from the date of coming in force of these Rules.

By order of the Governor of Bihar,
P. C. Chaudhary,
Secretary-cum-Legal Remembrancer.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 632-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>